



भारत की बदलती खाद्य अर्थव्यवस्था-खाद्य क्षेत्र में प्रदर्शन, संपर्क और सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच

Posted On: 27 FEB 2017 12:44PM by PIB Delhi

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज दोपहर भोजन पर भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपलब्ध निवेश अवसरों के बारे में विचार साझा करने के लिये प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य विक्रेता देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ बैठक की।

इस अवसर पर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा, 'हाल ही में भारत सरकार ने देश में उत्पादित और निर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन के लिए शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत के खाद्य प्रसंस्करण निर्माण, आपूर्ति और विपणन के क्षेत्र में निवेश के अधिक अवसर खुले हैं। इसके अतिरिक्त राज्य और केंद्र सरकारों ने आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए हैं, जिनमें पूंजी सब्सिडी, कर में राहत और सीमा शुल्क तथा आबकारी कर घटाना शामिल है। शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज), बूचड़खानों और फूड पार्क जैसे बुनियादी ढांचा से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके पीछे विचार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तेजी से वृद्धि और भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के साथ ही किसानों को अपनी मूल्यवान श्रृंखला से जोड़ना है ताकि उनको अधिक लाभ मिल सके।'

बातचीत के दौरान मंत्री महोदया ने मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर, 2017 को आयोजित किए जाने वाले तीन दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम - विश्व खाद्य भारत 2017 में साझेदारी के लिए इन देशों को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की उपलब्धियों और अवसरों तथा अधिकतम निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम से क्षेत्र के अभिनव उत्पादों और निर्माण प्रक्रियाओं की प्रौद्योगिकी, विकास और स्थिरता की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मूल्य श्रृंखला प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध होगा।

इस अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव ने कहा, 'देश में पर्योज्य आय बढ़ने और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण प्रसंस्करण खुदरा व्यापार और ई-वाणिज्य के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध है। पिछले दो वर्षों में भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ऊर्जावान वृद्धि के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। प्रगतिशील नीति के दृष्टि से नए सहयोग और अधिक निवेश को पूरा समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय और वैश्विक खाद्य एवं पेय क्षेत्र के बीच नजदीकी बातचीत आवश्यक है और विश्व खाद्य भारत 2017 से यह मंच उपलब्ध होगा।'

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में विशेष सचिव श्री जे पी मीणा ने कहा, 'भारत में पहले से ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अग्रणी शुरुआत की सभी जरूरत की सुविधा उपलब्ध है। खाद्यान्न, दाल, सब्जी, मांस और मछली जैसी मूल सामग्री स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपसी लाभ के लिए मूल्य श्रृंखला में इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के एकीकरण और सहयोग की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप निवेश से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में और मदद मिलेगी जिससे बर्बादी कम होगी और बाजारों के लिए किसानों को एकीकृत किया जा सकेगा। इस बैठक में डेनमार्क, फ्रांस, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, हॉलैंड, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, स्पेन, स्वीजरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम, ब्राजील और अमरीका के दूतावासों के राजदूतों के साथ ही कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड और बेल्जियम के उच्चायोग के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने मंत्रालय द्वारा विश्व खाद्य भारत 2017 कार्यक्रम आयोजित करने की पहल के लिए मंत्रालय की सहायता की और इस कार्यक्रम में शामिल होने की रुचि व्यक्त की।

वीके/एमके/एसके-541

(Release ID: 1483342) Visitor Counter : 11

